ISRJ

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 2 | MARCH – 2017

डिजिटल डिवाइड को खत्म करता डिजिटल मीडिया

रुपाली अलोने
शोधार्थी,पी-एचडी जनसंचार, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा.

सारांश

सूचना और तकनीक के इस युग में विकास और समृद्धि के सभी रास्ते भी सूचना के माध्यम से खुलते हैं। जिसके पास सूचना के जीतने ज्यादा श्रोत होंगे उसके विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सूचना के स्रोतों की उपलब्धता को लेकर संचार अध्ययन में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सूचना प्राप्ति के श्रोतों या संसाधनों की बात करता है। समाज का उच्च, शहरी और शिक्षित वर्ग कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तमाम अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इस वजह से उसके लिए सूचनाओं और संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरा वर्ग वह है जो इन संसाधनों से या तो अनभिज्ञ या बहुत कम इस्तेमाल करता है। इस तरह इन दोनों वर्गों के बीच एक बहुत बड़ी गैप है। स्पष्ट है कि संसाधनों की कमी वजह से एक व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र सूचना-समृद्ध हो जाता है तो दूसरा सूचना-दरिद्र रह जाता है। इस विभिन्नता को हम डिजिटल डिवाइड के रूप में देखते हैं। डिजिटल डिवाइड, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। देश के भीतर डिवाइड आमतौर पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तर या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में, व्यक्तियों, घर,व्यवसाय, या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है। उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो अमिर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में एक डिजिटल डिवाइड है। मगर आधुनिक युग डिजिटल क्रांति का युग है। पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया का भविष्य और स्वरूप तेजी से बदला है। इंटरनेट का बढ़ता प्रसार और डिजिटल मोबाइल की बढ़ती उपलब्धता ने सूचना के आधिपत्य को समाप्त कर दिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया की संकल्पना ने डिजिटल डिवाइड की वर्गभेदी संकल्पना को काफी कमजोर कर दिया है। इसकी वजह से विकास के रास्ते सबके लिए खुल गए हैं। यह शोध पत्र इस संकल्पना पर आधारित है। इस शोध पत्र में 'डिजिटल इंडिया' परियोजना के प्रसार एवं इससे हो रहे बदलाव पर भी दृष्टी डाली गई है।

शब्द-कुंजी : डिजिटल मीडिया, संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटललाईज, डिजिटल डिवाइड।

प्रस्तावना :

आधुनिक युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना क्रांति ने हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है इसकी झलक संचार के नित नए विकसित हो रहे माध्यमों में मिल जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंटरनेट इन नये माध्यमों का केंद्रबिंदु है। आज सूचनाओं का आदान-प्रदान और उन्हें पलक झपकते ही एक कोने से दुसरे कोने में पहुंचा देना अब बेहद आसान हो चूका है। अनुमानत: भारत में जून, 2015 की समाप्ति पर 35.4 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। पर आज डिजिटल इंडिया परियोजना के वजह से इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। मनुष्य धीरे-धीरे डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर रहा है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। डिजिटल इंडिया देश में इंटरनेट तक ही सिमटा हुआ नजर नहीं आएगा। ये एक ऐसे संसाधन के रूप में भी उभरकर सामने आता है जिसका प्रयोग पिछड़े और गुमनाम इलाको को भी राष्ट्रिय फलक पर लाने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया कई अवयवों से बना है, लेकिन सबसे बड़ा अवयव अंतिम मील तक कनेक्टिविटी हैं। जहां सरकार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त सेवा केंद्रों को फाइबर ऑप्टिकल के माध्यम से जोड़ने का काम शुरू किया गया है जो डिजिटल डिवाइड खत्म होने के एक अछि पहल है।

डिजिटल डिवाइड क्या है ?

दुनिया के समाज को दो भागों में बाँटा जा सकता है एक तो वह लोग या देश जिनके पास सूचनाओं का अम्बार होता है एवं आईसीटीज का भरपूर उपयोग करते हैं उसे विकसित समाज कहा जाता है और दुसरे वह लोग या देश जिनके पास सूचना संसाधन नहीं होते हैं एवं आईसीटीज के उपयोग से वंचित रहते हैं, उन्हें अविकसित समाज की श्रेणी में रखा जाता है. विकसित समाज के पास आगे और बढ़ने की क्षमता होती है ज्ञान ही समाज को आगे बढाता है एवं अज्ञानता समाज को पिछड़ेपन या गरीबी की और हमेशा ढकेलती रहती है इसे भाषा में “नॉलेज गैप” कहते हैं जिसे “डिजिटल डिवाइड” कहा जाता है इसमें कुछ सामाजिक कठिनाइयों के कारण एक समाज आईसीटीज का उपयोग नहीं कर पाता एवं दूसरा समाज इसका भरपूर उपयोग कर सकता है एवं विकास के क्षेत्र में हमेशा अग्रेसर रहता है.

कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने और संसाधनों की कमी के कारण उसको उपयोग में कम लाया जाता था जिसके कारण एक व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र सूचना-समृद्ध हो जाता था तो दूसरा सूचना-दरिद्र रह जाता था जिसे हम डिजिटल डिवाइड के रूप में देखते थे। डिजिटल डिवाइड, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। देश के भीतर डिवाइड आमतौर पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तर या अन्य जनसांख्यिकीय श्रेणियों में, व्यक्तियों, घर,व्यवसाय, या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है। उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो अमिर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित के बीच में एक डिजिटल डिवाइड है।

दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) फरवरी 2014 की एक रिपोर्ट में देखा गया है की देश में कुल 90 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 54 करोड़ शहरी और 35 करोड़ ग्रामीण हैं। इसका मतलब यही है की इंटरनेट उपभोक्ताओं में ग्रामीण लोगों की संख्या कम थी। वही इंटरनेट की बात करें तो 22 करोंड इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 15 करोड़ से ज्यादा ब्रोड्बैंड का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई के आकड़ों से पता चलता है की शहरों में दूरसंचार घनत्त्व 144 प्रतिशत है, जबकि देश के ग्रामीण इलाकों में यह 41 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया है। इस तथ्य से साफ़ जाहिर होता है कि दूरसंचार साधनों की उपलब्धता एक समान नहीं है। शहरों में बहुत ज्यादा है तो गावों में बहुत कम। डिजिटल डिवाइड शिक्षा, स्वास्थ, धन, गृह, रोजगार, साफ पानी एवं उचित खाद्य पदार्थ अदि को प्रभावित करती है.

डिजिटल डिवाइड के कारण :

1. आमदनी
2. शिक्षा
3. लिंग
4. भौगालिक क्षेत्र (ग्रामीण एवं शहरी)
5. उम्र
6. कौशल
7. जागरूकता
8. राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ती

डिजिटल डिवाइड खत्म करने में सरकार की डिजिटल इंडिया परियोजना

डिजिटल इंडिया क्या है ?

भारत सरकार ने डिजिटल माध्यमों का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य इन्ही प्रयासों का प्रस्थान बिंदु है। डिजिटल इंडिया का मकसद सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना ताकि बिना कागज के इस्तेमाल से सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रोनिक रूप से जनता तक पहुँच सके। ऑनलाईन किताबों के लिए ई-बस्ता, दस्तावेज सेव करने के लिए ई-लॉकर, ई-हॉस्पिटल, विभिन्न शहरों में वाई-फाई और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लांच हो गए है।

डिजिटल इंडिया एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी काम काज में पारदर्शिता के साथ-साथ सभी सेवायें जनसामान्य तक तत्काल पहुँचाई जा रही है। ई सेवाओं के विस्तार के कारण बिचौलियों/ दलालों का खात्मा हो रहा है। एक वक्त ऐसा था जब छोटी-छोटी काम के लिए बहुत से लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते थे अब वह भी बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। दफ्तरों में कर्मचारियों को समय सीमा में बांध दिया गया है, जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी काम में लेट-लतिफी और रिश्वतखोरी में पारदर्शिता दिखाई देगी।

आज डिजिटल मीडिया के वजह से इंटरनेट पर सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी में उपलब्ध है चाहे वह किसानों से सम्बंधित हो या मनरेगा से। आयकर भरने के साथ-साथ बिजली, पानी, फोन, बिमा आदि के लिए भुगतान करने से लेकर नौकरी के लिए फॉर्म भरने रिझल्ट देखने एवं आय-जाति निवास प्रमाणपत्र बनवाने जैसे काम गुड गवर्नंस के माध्यम से इंटरनेट द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकते है।

डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य :

डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलकर, तकनीकी तौर पर सशक्त, सक्षम समाज को तैयार करना है। सर्वांगीण विकास के लिए डिजिटल इंडिया ने केवल जनोपयोगी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण का मार्ग प्रशस्त करता है, वरन ग्रामीण और नगरीय जीवन शैली के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म कर पब्लिक डाटा के संग्रहण से भारत के डिजिटल ब्लूप्रिंट के रूप में सूचनाओं को आंमंत्रित भी करता है। आज ऐसे कई स्मार्ट एप्लीकेशन बन रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ, प्रशासनिक सेवाओं, विनियम, यातायात आदि क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत के सभी स्कूलों को वाई-फाई से जोड़कर, वृहद ज्ञान तंत्र खड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही स्तरीय पाठ्य सामग्री, ग्रामीण भारत के बच्चों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत से सभी तबके के युवाओं के लिए स्तरीय शिक्षा तक पहुँच सुलभ होगी। भारत की 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार छः से आठ वर्ष की उम्र के

बीस प्रतिशत बच्चों को शब्द और संख्याओं का ज्ञान नहीं था। “गल्ली-गल्ली सिम-सिम” नामक एक अनूठी पहल के अंतर्गत बिहार और दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों को ‘फन एंड लर्न’ एप्लीकेशन के उपयोग से उत्साहजनक परिणाम सामने आए है।

डिजिटल इंडिया के वजह से आज रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हो रही है जिसको हम ‘मेक इन इंडिया’ के माध्यम से देख रहे है। ‘मेक इन इंडिया’ का आशय है कि ऐसी वस्तुओं या उत्पादों से है जिसका निर्माण भारत में होगा, जिससे उनकी कीमत कम होगी। विदेशों से वस्तुओं का आयात करने से उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पादों को विदेश से लाने में हुए खर्च को भी उत्पादों की कीमत में शामिल किया जाता है। अगर वस्तुओं का निर्माण देश में होगा तो देश के लोगों की जरुरत तो पूरी होगी ही, साथ ही साथ निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा आएगी, आय में इजाफा, अंतर्देशीय व्यापार में मुनाफा, सरकारी खजाने में बढोतरी, विकास दर में इजाफा, अर्थव्यवस्था में मजबूती, रोजगार दर में वृद्धि होना संभव है। सरकार चाहती है की ‘मेक इन इंडिया’ के मदद से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़कर 16 से 25 प्रतिशत, 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन, घरेलू मूल्य संवर्धन आदि संभव है। ‘मेक इन इंडिया’ के लिए प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने ‘इंवेस्ट इन इंडिया’ नाम की वेबसाइट लांच की है। स्टार्ट अप इंडिया मेक इन इंडिया की अगली कड़ी है।

डिजिटल इंडिया के फायदे :

1. डिजिटल लॉकर : डिजिटल लॉकर को खोला जा रहा है जिसमें हम हमारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र से लेकर जरुरी कागजों को हम इसमें रख सकते है। जिस वजह से हमें प्रमाणपत्रों को संभालके रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। प्रमाणपत्रों को बार-बार फोटोकॉपी कराने, उसे अप्रूव करने कराने और प्रमाण पत्रों के घूम होने की आशंका से मुक्ति मिलेगी। नौकरी वगैरह के लिए जब भी जरूरत होगी, इस लॉकर लिंक देकर काम चलाया जा सकेगा।

2. लैंडलाइन से वीडियो कॉल ई-मेल : लैंडलाइन अब केवल बातचीत के लिए ही नहीं उपयोग में लाया जाएगा बल्कि उससे हम वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-मेल कर सेकेंगे। हमारा मोबाइल फोन हमारे लैंडलाइन से घर-ऑफिस जाते ही अपने आप लिंक हो जाएगा।

3. ई हॉस्पिटल : ई हॉस्पिटल के वजह से ओपीडी में डॉक्टर से मिलना आसान होगा। हम ऑनलाइन डॉक्टर से मिलने का दिन, समय मिलेगा। एम्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसका यह फायदा हो रहा है कि जो दूर-दराज से आने वाले मरीजों को लाइन में लगने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।

4. ई हैल्थ : विशेषज्ञ डॉक्टरों से गांव-देहातों में टेली मेडिसीन के जरिए चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। इसमें फीस भी कम होगी। इस सुविधा से मरीज को बार-बार शहर आने, बड़े डॉक्टरों से समय नहीं मिलने, नीम-हकीमों से निजात मिल सकेगी।

5. ई अपॉइंटमेंट : डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना आसान होगा। संबंधित मंत्रालय-विभागों के पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ई-मेल द्वारा हमें अपॉइंटमेंट की सूचना मिल सकेगी। इससे यह फायदा होगा कि अधिकारी लगातार मिलने से मना नहीं कर पाएंगे। हमारे पास यह रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने कितनी बार मिलने का समय मांगा था।

6. ई बैग : विद्यार्थी स्कूली किताबों को टैब-लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड कर पाएंगे। पहले चरण में यह सीबीएसई (CBSE) के 10वीं और 12वीं कक्षाओं में लागू होगा। एनसीईआरटी की कुछ कक्षा की किताबों में इसका लाभ लिया जा रहा है।

7. रोजगार: सरकार ने यह दावा किया है कि इस योजना से करीब 18 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8. मोबाईल ऐप : MYGOV और स्वच्छ भारत मिशन की मोबाईल एप्लीकेशन लांच की जारही है। जिनके जरिये आप सरकार से सीधे अपने मोबाईल के जरी जुड़ सकेंगे।

9. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम- इसका सबंध स्कुल-कॉलेज में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाजिरी से है।

10. इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन - सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जो के आयत को शून्य करना है।

11. इन्फोर्मेशन फॉर ऑल- यानी सभी को ऑनलाईन जानकारियां मुहैया कराई जा रही है।

12. ब्रॉडबैंड हाइवे- भारत सरकार ने भारत नेट नाम की एक पहल शुरू की है, यह देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का एक उच्च गति डिजिटल राजमार्ग है. ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है ।

रूरल-अर्बन डिवाइड :

डिजिटल इंडिया के केंद्र में भारतीय नागरिक है क्योंकि भारत गावं में बसता है और किसान भारत के आधार स्तंभ है। डिजिटल इंडिया को सफल बनाने एवं निचले स्तर तक सरकार के ई-शासन की पहुँच को सुलभ करने में सबसे बड़ी चुनौती है की ग्रामीण अंचल के लोगों को अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों एवं एप आदि से साक्षर बनाया जाए । क्योंकि गावों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर शहरों के मुकाबले काफी कमजोर है। यही कारण है कि देश में इंटरनेट का उपयोग करने वाली गरीब 23 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और जब तक देश का हर आम व्यक्ति ई-शासन की तकनीकी प्रक्रिया को समझने में सक्षम नहीं होगा तब तक डिजिटल इंडिया मिशन का पूरा लाभ मिलना संभव नहीं है। राष्ट्रिय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रही है । इसके तहत 10 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को मोबाईल एप-एवं वेब-पोर्टल्स आदि से जुड़ी जानकारियां दी जा रहीं है। इंटरनेट की पहुँच और स्पीड को प्रभावी करने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत वर्ष 2020 तक देशभर में 60 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 फीसदी टेलीडेंसिटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एक समय था गावं में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए घर से बाहर या छत पर जाना पड़ता था पर आज स्थिती बदल चुकी है डिजिटल इंडिया परियोजना के वजह से यह संभव हो रहा है । गावं में नेटवर्क कनेक्टिविटी से राहत मिली है। इस पहल में 2.5 लाख गावं को हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड एवं फोन से जोड़े जारहे है। इसका उदहारण है आदिवासी बहुल मेलघाट का 'हरिसाल गावं' जो डिजिटल विलेज से जाना जाता है। यह देश का पहला ऐसा गावं है जो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चूका है। इस गावं में 3 जी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा दी गई है साथ में गावं के हर व्यक्ति को एटीएम. और डेबिट कार्ड दिए गए है। हाल ही में वहां कैशलेस इकनोमि को प्रोत्साहित करने पेटीएम और महा ई-सेवा केंद्र का शुभारंभ भी किया गया है।

कई ऐसे एप है जो केवल ग्रामीण क्षेत्र को के लिए बनाए गए है। ग्रामीण भाग में महिलाओं का गिरता स्वास्थ और कुपोषण जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है इससे निपटने के लिए सरकार ने 'आरोग्य सखी' नाम एक मोबाईल एप्लीकेशन लांच किया है। इसका मुख्य हेतु महिलाओं को उनकी गर्भावस्था और उसके पश्चात् समुचित स्वास्थ सुविधा देने के लिए भी हो रहा है।

किसानों के लिए मोबाईल एप :

हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं शहरीकरण तेजी से होने के बावजूद भी देश का बड़ा वर्ग अभी भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। आज किसान के पास भी स्मार्टफोन की पहुंच हो गई है ऐसे में उनके लिए कुछ एप्स बनाए गए है जिसके मार्फ़त उन्हें सूचना का प्रसारण हो सके। जैसे 1) खेती-बाड़ी-जैविक खेती एप 2) किसान मित्रा 3) किसान सुविधा 4) एग्रो कनेक्ट किसान एग्री एप (AGROCONNECT KISAN AGRI APP) ।

निष्कर्ष :

सूचना क्रांति ने हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। तकनीकी तौर पर इसकी झलक संचार के नित नए विकसित हो रहे माध्यमों में मिल जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है की इंटरनेट इन नए माध्यमों का केंद्रबिंदु है। सूचनाओं का आदान-प्रदान और उन्हें पलक झपकते ही एक कोने से दुसरे कोने मे पहुंचा देना अब बेहद आसाम हो चूका है। 'डिजिटल इंडिया' का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की विशाल दुनिया से जोड़कर ग्लोबल बनाने का है। इस परियोजना का न सिर्फ सामाजिक पहलू है बल्कि व्यावसायिक पहलू भी है।

वर्तमान में डिजिटल डिवाइड संकल्पना खत्म होते दिखाई दे रहीं है। मोबाईल बैंकिंग तथा आर्थिक व्यवहार के लिए डिजिटल भुगतान (कैशलेस व्यवहार) सुविधा उपलब्ध है। जिसके लिए 'डिजिशाला' चैनल की शुरुआत की गई है। इसके जरिए ग्रामीण और अर्ध्दशहरी क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति शिक्षित किया jaa रहा है। मोबाईल पर पेटीएम, ई-वॉलेट, एसबीआई बड़ी जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल भुगतान किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास को समर्पित (फरवरी 2016 और मई 2016)
2. योजना, विकास को समर्पित मासिक (जनवरी 2016 और जून 2016)
3. दैनिक भास्कर, (रसरंग) 23 अगस्त 2016
4. दैनिक भास्कर, 10 दिसंबर 2016
5. दैनिक भास्कर, 20 नवंबर 2016
6. दैनिक भास्कर 9 दिसंबर 2016
7. http://hindi.indiawaterportal.org/node/54208
8. http://www.bbc.com/hindi/international/2015/09/